भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2082
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

देश में रोजगार सृजन

2082. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दस वर्षों के दौरान देश में रोजगार सृजन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत दस वर्षों के दौरान निजी एवं सरकारी क्षेत्र में सृजित नौकरियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत दस वर्षों के दौरान रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक पहल के अंतर्गत रोजगार सृजन के मामले में क्या प्रगति हुई है;
- (घ) सरकार द्वारा किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है तथा देश में रोजगार सृजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और
- (ङ) क्या उत्तराखंड, गुजरात और त्रिपुरा राज्यों ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को क्रियान्वित किया है, यदि हां, तो सरकार की योजनाओं के परिणामस्वरूप सृजित नौकरियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकारिक स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्रदर्शन) 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है।

विधायी सुधारों के एक भाग के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को चार संहिताओं में मिला दिया गया है। सभी संहिताओं को अर्थात्, मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य

स्थिति संहिता, 2020 संसद द्वारा पारित और अधिसूचित किया गया है। इन संहिताओं का उद्देश्य प्रत्येक कामगार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार अवसरों के सृजन को उत्प्रेरित करना है जो इस प्रकार है:

- सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालन दबाव में कमी के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना
- फैक्टरी लाइसेंस, अनुबंध श्रम लाइसेंस, छंटनी के लिए पूर्व अनुमति, कामबंदी और बंदी तथा स्थायी आदेशों के प्रमाणन के लिए सीमा सीमा बढ़ाना।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। तदनुसार, सरकार उत्तराखंड, गुजरात और त्रिपुरा राज्यों सहित देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आदि भी शामिल हैं।

सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की। इसमें 1,07,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल है, जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।